उत्तर प्रदेश
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

ई-संदेश

07 जुलाई 2021, वर्ष 4, अंक 146

सात दिन – सात पृष्ठ

सुल्तानपुर में वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत पौधा लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

- ★ 4 वर्ष के दौरान जिन पौधों का रोपण किया गया, उसमें से 75 से 90 प्रतिशत पौधे जीवित और पूरी तरह सुरक्षित
- ★ नगर निगम अयोध्या में 852.57 लाख रु की लागत से कान्हा गौशाला विकसित की जा रही
- ★ समय-सीमा और लक्ष्य निर्धारित कर गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं
- ★ प्रदेश में सवा चार लाख सरकारी नौकरियां तथा डेढ़ करोड़ से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला
- ★ सभी के सहयोग से कोरोना के दो चरणों के विरुद्ध मजबूती से लड़ाई लड़ी गयी
- ★ नये भारत का नया उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर और नया गोरखपुर आपकी पहचान है
- ★ प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी ढंग से किया जाए
- ★ प्रदेश सरकार 100 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज वृक्ष के रूप में मान्यता दे रही
- ★ स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण तथा वायु प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए सभी लोग जागरूक हों
- ★ 'हर घर जल' योजना हमारी प्राथमिकता
- ★ चित्र प्रदर्शनी

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

कोरोना हारेगा भारत जीतेगा

4 वर्ष के दौरान जिन पौधों का रोपण किया गया, उसमें से 75 से 90 प्रतिशत पौधे जीवित और पूरी तरह सुरक्षित : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के जितने अधिक सान्निध्य में हम सभी रहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की उतनी अधिक क्षमता हमारे पास होती है। जब भी हमने प्रकृति के विपरीत आचरण किया और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, उसका दुष्परिणाम पूरी जीव सृष्टि को भुगतना पड़ा। प्रकृति और पर्यावरण के समन्वय के महत्व का अनुमान हम वर्तमान में लगा सकते हैं, पूरी दुनिया विगत सवा वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रही है। चूंकि मनुष्य इस जीव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, वह ही सर्वाधिक इसकी चपेट में भी आया है।

मुख्यमंत्री सिटी मान्टेसरी स्कूल की गोमती नगर विस्तार शाखा के प्रांगण में पीपल के पौधे को रोपित कर प्रदेश में वन महोत्सव का शुभारम्भ करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव का कार्यक्रम हमारे लिये केवल वृक्ष लगाने तक ही सीमित नहीं है, अपितु प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारे दायित्व के निर्वहन का अवसर है। उन्होंने कहा कि पीपल का पवित्र पौधा लगाकर वन महोत्सव का शुभारम्भ किया गया है। पीपल भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान बुद्ध को इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए यह बोधि वृक्ष भी कहलाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, इसलिए वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष वृक्षारोपण के एक सुनिश्चित अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वृक्षारोपण के इस अभियान को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद वर्ष 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण तथा वर्ष 2018 में 11 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा किया गया। वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने प्रदेश की आबादी के बराबर एक ही दिन में निर्धारित 22 करोड़ वृक्षों के रोपण के लक्ष्य को पूरा किया। विगत वर्ष 2020 में कोरोना महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद एक दिन में प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाये गये। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में प्रदेश सरकार ने वन महोत्सव के दौरान 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 30 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष 4 जुलाई को एक ही दिन 25 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन विभाग सहित ग्राम्य विकास, पंचायती राज, लोक निर्माण, शिक्षा आदि प्रदेश शासन के अन्य विभाग अहिर्निश प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी से कोरोना महामारी से बचाव के निर्धारित प्रोटोकाल का पालन करते हुए, वृक्षारोपण महा अभियान के साथ जुड़ने की अपील की। राज्य सरकार 30 करोड़ पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ सभी प्रदेशवासियों को इस वृहद अभियान से जोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से दिवंगत हुए लोगों की स्मृति में ग्राम पंचायतों में पौधे रोपित किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नेशनल डाक्टर्स डे भी है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे चिकित्सकों ने जिस प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी के साथ मानवता की सेवा की है। वह अपने आप में एक उदाहरण है। इस अवसर पर उन्होंने सभी चिकित्सकों को नेशनल डाक्टर्स डे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश में वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। पिछले 4 वर्ष के दौरान जिन पौधों का रोपण किया गया, उसमें से 75 से 90 प्रतिशत पौधे जीवित और पूरी तरह सुरक्षित हैं। बहुत अच्छी वाटिकाएं और पेड़ आज वहां उगे हुए दिखायी देते हैं। इससे प्रदेश में वन का आच्छादन बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 100 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को हेरिटेज वृक्ष के रूप में संरक्षित करने का एक अभियान चलाया जा रहा है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में गंगा उद्यान लगाने की कार्यवाही की जा रही है। एक्सप्रेस–वे और हाईवे को इस बार वृक्षारोपण अभियान से जोड़ने जा रहे हैं। राम वन गमन मार्ग को वृक्षारोपण से आच्छादित करने की कार्यवाही चल रही है।

नगर निगम अयोध्या में 852.57 लाख रु की लागत से कान्हा गौशाला विकसित की जा रही : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के सुनियोजित नगर विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को तेजी से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों सहित अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नगरीय अवस्थापना को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने सभी परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अयोध्या नगर निगम में सीवरेज ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी, सीवर लाइन तथा सीवर हाउस कनेक्शन की वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं तथा आवश्यकता के अन्तर को पूर्ण करने के लिए डीपीआर 2 चरणों में प्रस्तुत किये जाएंगे। प्रथम चरण में 150 किलोमीटर सीवर लाइन तथा 20 हजार घरों हेतु सीवर कनेक्शन हेतु प्रस्ताव किया गया है। इसकी अनुमानित लागत 280 करोड़ रुपये है। द्वितीय चरण में सीवरेज ट्रीटमेन्ट सुविधा, 191.48 किलोमीटर सीवर लाइन तथा 20,316 घरों हेतु सीवर कनेक्शन का प्रस्ताव है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 320 करोड़ रुपये है। सरयू नदी में गिरने वाले नालों में से 3.5 एमएलडी के 5 नालों की टैपिंग की जा चुकी है। 15 नालों की टैपिंग के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत एनएमसीजी द्वारा 221.66 करोड़ रुपये की डीपीआर स्वीकृत की गयी है। नगर निगम में सभी घरों तक वाटर सप्लाई कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 105 करोड़ रुपये की धनराशि से लगभग 20,000 घरों को वाटर कनेक्शन उपलब्ध कराए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि नगर निगम अयोध्या में अमृत योजना के अन्तर्गत 07 पार्कों का विकास कराया जा रहा है। इनमें से 5 पार्कों का विकास कार्य पूर्ण हो गया है। राजद्वार पार्क 80 प्रतिशत तथा अश्वनीपुरम कालोनी पार्क का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम सहित 3 अन्य निकायों को 10.052 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करायी गयी है। यह भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु उपयुक्त पायी गयी है। इसमें लैण्ड फिलसाइट एवं प्लाण्ट स्थापित किया जा सकता है।

नगर निगम अयोध्या हेतु आईटीएमएस परियोजना स्वीकृत की गयी है। परियोजना की लागत 49.74 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए 12.42 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। परियोजना के तहत एडाप्टिव ट्रैफिक कण्ट्रोल सिस्टम, आटोमैटिक नम्बर प्लेट रिकगनिशन सिस्टम, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इमरजेन्सी काल बाक्स, सिटी वाईफाई, आपरेशन कण्ट्रोल रूम आदि विकसित किये जाएंगे। परियोजना के अक्टूबर, 2021 में क्रियाशील होने की सम्भावना है।

स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत मल्टीलेवल स्मार्ट पार्किंग विकसित करने की कार्यवाही भी की जा रही है। नगर निगम में कान्हा गौशाला विकसित की जा रही है, इसकी लागत 852.57 लाख रुपये है। नगर निगम अयोध्या द्वारा मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेन्टर क्रियाशील कराया गया है। इस परियोजना की लागत 38.42 लाख रुपये है। एमआरएफ सेन्टर में शेड, टायलेट, बाउण्ड्रीवाल, टूलरूम तथा वाशिंग एरियाध्पार्किंग एरियाध्ड्राइंग एरिया का निर्माण कराया गया है। सेन्टर में विगत तीन माह से कूड़े के पृथकीकरण का कार्य मैनुअल सम्पादित किया जा रहा है। सेन्टर में आवश्यक इक्युप्मेन्ट आपूर्ति की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में सेन्टर में इंसीनरेटर स्थापित करा दिया गया है। एमआरएफ सेन्टर 15 अगस्त, 2021 से सेमी आटोमैटिक रूप से क्रियाशील हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 30 जून, 2021 तक 6,112 आनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त हुए। 3,337 को लोन स्वीकृत किया गया तथा 3,167 को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है।

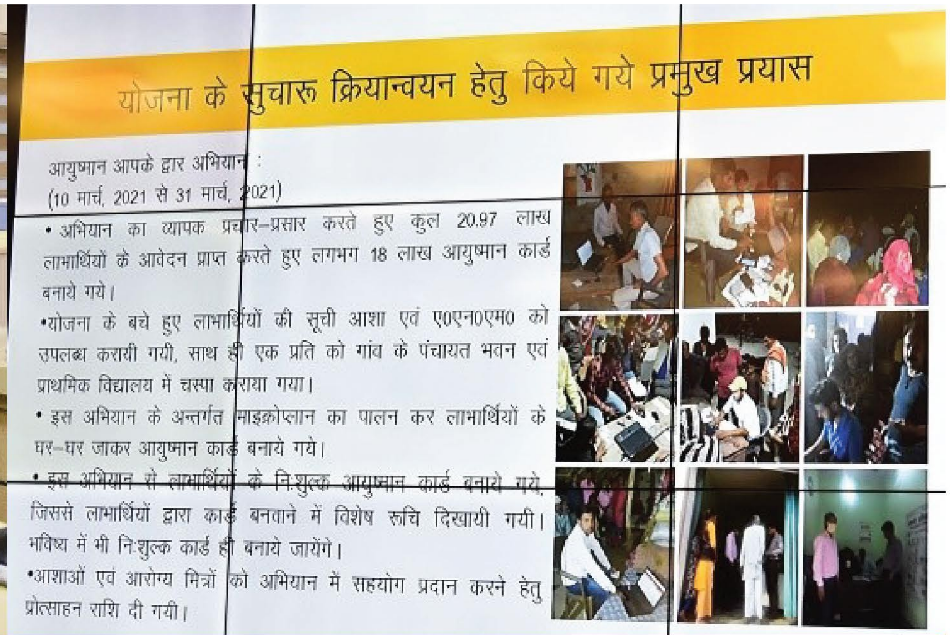

समय–सीमा और लक्ष्य निर्धारित कर गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत विशेष अभियान चलाकर सभी पात्रों को गोल्डन कार्ड तेजी से वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी गांवों और छूटे हुए लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड से आच्छादित किया जाए। समय–सीमा और लक्ष्य निर्धारित कर गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को गोल्डन कार्ड वितरित किए जाने निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर आयुष्मान भारत योजना तथा सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया बाहुल्य राजस्व ग्रामों में भी जागरूकता अभियान चलाकर गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने गोल्डन कार्ड बनाए जाने के विशेष अभियान से आशा बहुओं, एएनएम एवं आरोग्य मित्रों को जोड़ने की बात कही। उन्होंने योजना के प्रचार–प्रसार एवं गोल्डन कार्ड बनाए जाने हेतु मोबाइल मेडिकल यूनिट तथा नवनिर्वाचित प्रधानों का सहयोग लिए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी अन्त्योदय कार्डधारकों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किडनी ट्रांसप्लाण्ट, कार्नियल ट्रांसप्लाण्ट एवं म्यूकर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) के उपचार के पैकेज को योजना में सम्मिलित किए जाने पर विचार किया जाए। आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्डविहीन ग्रामों और परिवारों को चिन्हित करते हुए उनके गोल्डन कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उपचार व चिकित्सा के सम्बन्ध में भौतिक सत्यापन भी किया जाए, जिससे किसी गड़बड़ी की आशंका न रहे। आयुष्मान भारत योजना के तहत समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण किया जाए। इसी प्रकार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निर्धारित समय–सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाए। निर्माण कार्यों को मानक के अनुसार गुणवत्तापरक ढंग से पूरा कराया जाए। उन्होंने इस सम्बन्ध में मंत्रिगणों एवं उच्चाधिकारियों को मौके पर जाकर निर्माण कार्यों की प्रगति से अवगत होने की बात कही। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। उन्होंने इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता या विलम्ब पाए जाने पर जवाबदेही तय किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अस्पतालों तथा सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध रहें। चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण करते हुए वहां साफ–सफाई रखी जाए। मानव संसाधन के प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड विहीन ग्रामों को चिन्हित कर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। 10 से 31 मार्च, 2021 तक लगभग 18 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए। योजना से बचे हुए लाभार्थियों की सूची के अनुसार कार्ड वितरण की कार्यवाही की जा रही है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को योजना के प्रचार–प्रसार हेतु पत्र प्रेषित कर योजना में सहयोग का अनुरोध किया गया है। गोल्डन कार्डधारकों को सुविधाएं एवं लाभ प्राप्त करने के विषय में एसएमएस के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि निजी मेडिकल कालेजों में कोविड से ग्रसित लाभार्थियों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने वाले मेडिकल कालेजों को आयुष्मान भारत की दरों पर भुगतान किया गया है। जून, 2021 तक कुल 29,827 उपचारित लाभार्थियों के सापेक्ष 56.42 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

प्रदेश में सवा चार लाख सरकारी नौकरियां तथा डेढ़ करोड़ से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले सवा चार वर्षों में प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन आया है। प्रदेश में एक नयापन देखने को मिल रहा है। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश की स्थिति को बदलता हुआ देखा जा रहा है। प्रदेश में सवा चार लाख सरकारी नौकरियां तथा इससे कई गुना अधिक निजी नौकरियां प्रदान की गईं। प्रदेश में निजी निवेश के कारण डेढ़ करोड़ से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। इसके माध्यम से युवाओं को स्वावलम्बन की ओर अग्रसर होने का अवसर प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री लोक भवन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जेल वॉर्डर (पुरुष), जेल वॉर्डर (महिला), फायरमैन एवं घुड़सवार पुलिस के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तिध्चयन पत्र वितरित करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नवचयनित 5,805 अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जेल वॉर्डर की चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत जेल वॉर्डर (महिला) चयनित की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सवा चार वर्षों के दौरान ईमानदारी एवं पारदर्शी ढंग से डेढ़ लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को सम्पन्न किया गया। इससे वर्तमान प्रदेश सरकार की नई कार्य पद्धति के साथ एक नए उत्तर प्रदेश का मानचित्र प्रस्तुत हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जेल वॉर्डर (पुरुष), जेल वॉर्डर (महिला), फायरमैन एवं घुड़सवार पुलिस के पद की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। इस चयन प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात यह रही कि प्रत्येक जनपद के अभ्यर्थियों ने इस प्रक्रिया में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि वे सभी 5,805 सफल अभ्यर्थियों से संवाद करना चाहते थे, किन्तु कोविड प्रोटोकाल का पालन करने के कारण एक साथ सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बुलाना सम्भव नहीं था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर सुधार दिखायी दे रहा है। यह बदलाव टीम वर्क के कारण ही सम्भव हो सका है। इसमें पुलिस महानिदेशक से लेकर आरक्षी तक तथा शासन–प्रशासन के प्रत्येक व्यक्ति के सामूहिक प्रयास से राज्य की छवि को बदलने में सफलता मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट–2018' में राज्य को साढ़े चार लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें से अधिकतर लागू हो गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था से निवेश का माहौल बना, युवाओं के लिए रोजगार की सम्भावनाएं आगे बढ़ीं। निजी क्षेत्र में हमारे प्रदेश के युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरियां और रोजगार प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों से कहा कि नियुक्ति के पश्चात् जो वेतन मिलेगा, वह प्रदेश की जनता का पैसा है। टैक्स के रूप में प्रदेश की जनता के इस सहयोग से विकास भी होता है और व्यवस्था का संचालन भी। इसलिए जनता के प्रति आप सभी की जवाबदेही है। उन्होंने नवचयनित कर्मियों से अपेक्षा की कि वे पूरी ईमानदारी एवं प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सेवा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने स्वयं जेल वॉर्डर (पुरुष), जेल वॉर्डर (महिला), फायरमैन एवं घुड़सवार पुलिस के पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्तिध्चयन पत्र वितरित किए। इनमें जेल वॉर्डर (पुरुष) के लिए अभिषेक पाल, अतुल कुमार एवं संदीप कुमार, जेल वॉर्डर (महिला) के लिए प्रीति सिंह, वैशाली देवी एवं पूजा देवी, घुड़सवार पुलिस के लिए प्रमोद कुमार मौर्य एवं मृत्युंजय लोहिया तथा फायरमैन के लिए विवेक सिंह, शिवेन्द्र शर्मा, अजय वर्मा एवं शुभम कुमार शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह् एवं रूद्राक्ष का पौधा भेंट किया गया।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आयी है, तब से प्रदेश में रूल ऑफ लॉ का प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला है, जिसकी लोग वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रत्येक क्षेत्र में हुए सुधारों से एक व्यावहारिक परिवर्तन आया है। पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में नौकरियां और बड़े पैमाने पर कार्मिकों को प्रोन्नति का अवसर मिला है। प्रदेश सरकार ने पुलिस ड्यूटी और प्रोन्नति की विसंगतियों को दूर किया।

सभी के सहयोग से कोरोना के दो चरणों के विरुद्ध मजबूती से लड़ाई लड़ी गयी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी के सहयोग से कोरोना के दो चरणों के विरुद्ध मजबूती से लड़ाई लड़ी गयी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक नियन्त्रित किया गया है। दूसरे चरण में आयी चुनौतियों का सभी ने मिलकर सामना किया, जिसके फलस्वरूप पूरे प्रदेश में विगत 24 घण्टों के दौरान मात्र 112 नये कोविड पाजिटिव केस आये हैं और कुल 2461 एक्टिव केस शेष हैं। उन्होंने उम्मीद जतायी कि इस गति से हम कुछ ही दिनों में इस दूसरे चरण पर भी नियन्त्रण पाने में सफल होंगे। इसी प्रकार कोविड की तीसरी वेव की आशंका के दृष्टिगत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ तैयारियां की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर फ्लिपकार्ट द्वारा 30 क्रिटिकल केयर वेण्टीलेटर्स प्रदान किये जाने के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। यह वेण्टीलेटर्स उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लि (यूपीएमएससीएल) को दिये गये हैं। उन्होंने फ्लिपकार्ट द्वारा संकट और जरूरत के समय उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ जुड़े रहने की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन वेण्टीलेटर्स के माध्यम से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने के साथ–साथ जरूरतमंद मरीजों तक सही समय पर क्रिटिकल केयर पहुंचाने में मदद मिलेगी। कोरोना के आरम्भ काल में पीपीई किट्स तथा एन–95 मास्क की समस्या थी, जिसका समाधान करने में भी फ्लिपकार्ट ने सहायता की। इस प्रकार कोरोना वारियर और हेल्थ वर्कर्स के लिए जरूरी चीजों को उपलब्ध कराने में भी फ्लिपकार्ट ने सहयोग किया। 'एक जनपद, एक उत्पाद' (ओडीओपी) के तहत उत्पादों की सप्लाई चेन को बढ़ाने और उनकी मार्केटिंग करने में भी फ्लिपकार्ट द्वारा सफलतापूर्वक कार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कोरोना पर नियन्त्रण के नजदीक हैं, किन्तु अभी भी सावधानी और सतर्कता जरूरी है। आवागमन और आर्थिक, सामाजिक गतिविधियां संचालित हो चुकी हैं। कोरोना की तीसरी वेव में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा युद्धस्तर पर पीकू वार्ड की स्थापना की जा रही हैं। सभी मेडिकल कालेजों में 100–100 बेड तथा सभी जिला चिकित्सालयों में 25 से 30 बेड के पीकू वार्ड बनाये जा रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जनपद में 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) पर मिनी पीकू निर्मित हो रहे हैं। बच्चों के लिए उनकी आयु वर्ग के अनुसार निगरानी समितियों के माध्यम से मेडिसिन किट का वितरण किया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है।

फ्लिपकार्ट के चीफ कारपोरेट अफेयर्स आफिसर रजनीश कुमार ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अवसर पर कहा कि फ्लिपकार्ट समय–समय पर कोविड राहत कार्यों के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराने तथा इस महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन आईसीयू वेण्टीलेटर्स से राज्य सरकार को कोविड के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। रजनीश कुमार ने कहा कि तकनीक और ई–कॉमर्स के माध्यम से लघु उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने में भी फ्लिपकार्ट तेजी से कार्य कर रहा है। एमएसएमई से जुड़कर फ्लिपकार्ट ने सप्लाई चेन को मजबूत किया है। रोजगार के अवसर सृजित किये हैं। साथ ही, निर्यात के माध्यम से आय को बढ़ाने में भी सहयोग किया है। उन्होंने आश्वस्त किया भविष्य में भी इसी प्रकार फ्लिपकार्ट और उसकी टीम द्वारा स्वास्थ्य सहित जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सहयोग प्रदान किया जाता रहेगा। अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल ने कार्यक्रम का संचालन किया।

नये भारत का नया उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर और नया गोरखपुर आपकी पहचान है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में गोरखपुर शहर, पिपराइच एवं कैम्पियरगंज विधान सभा क्षेत्र की कुल 16197.35 लाख रुपए की लागत की 71 परियोजनाओं का लोकार्पणधशिलान्यास किया। इनमें 3222.55 लाख रुपए की लागत की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 12974.80 लाख रुपए की लागत की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। शिलान्यास की गई परियोजनाओं में गोरखपुर में 5405.34 लाख रुपए की लागत से नए कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण कार्य भी शामिल है।

महायोगी बाबा गम्भीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग सवा साल से जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त थी, तब हमारे देश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता प्राप्त करते हुए जीवन बचाने के साथ ही लोगों की जीविका को भी बचाया। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में देश को कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में शासन–प्रशासन, जनप्रतिनिधि, हेल्थ वर्कर्स आदि सभी ने 'सेवा ही संगठन' के संकल्प के साथ कार्य किया है, जिसका परिणाम है कि हमने कोरोना महामारी की चुनौती को जीता है। सरकार ने जीवन व जीविका को बचाने के भाव के साथ कार्य किया है। कोरोना का सामना करते हुए प्रदेश में विकास की गति को रुकने नहीं दिया गया और विकास की गतिविधियां जारी रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नये भारत का नया उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर आप सबके सामने है और नया गोरखपुर आपकी पहचान है। उन्होंने कहा कि अच्छी छवि बनाने के लिए प्रयासधपरिश्रम करना पड़ता है। गोरखपुर विकास की प्रक्रिया में निरन्तर आगे बढ़ रहा है। नए गोरखपुर की छवि को बनाए रखना, विकास की सोच को बढ़ाना तथा विकास के साथ जुड़ना हम सभी का दायित्व है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में निरन्तर विकास को गति मिल रही है। जनपद के बीआरडी मेडिकल कालेज में जहां एक ओर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर गोरखपुर में एम्स का निर्माण भी पूर्ण होने वाला है, जिसका लोकार्पण अक्टूबर माह तक प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव आवश्यक है, क्योंकि यह महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना के लक्षण दिखते ही टेस्टिंग कराएं और वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। सरकार द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का कवच है। बीमारी को छिपाने के बजाए, उसकी जांच करायी जाए, ताकि समय से बीमारी का उपचार हो सके। प्रदेश सरकार ने कोरोना की लड़ाई लड़ने के साथ ही विकास के पहिये को थमने नहीं दिया। प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी एक नए रूप में निखर रही है और अगले पांच वर्ष में उत्तर प्रदेश, देश की पहली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है और कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। यहां कानून का राज है और यही कारण है कि आज प्रदेश में उद्यमी अधिक से अधिक निवेश कर रहे हैं। यहां सिंगल विण्डो सिस्टम लागू है। प्रदेश में चार लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान प्रशासन द्वारा जीवन बचाने की दिशा में किए गए सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विकास की नई सोच के साथ सभी को आगे बढ़ना है। नौजवानों को सिविल सेवा, पुलिस सेवा, इंजीनियरिंग, सहित विभिन्न क्षेत्रों में तैयारी हेतु उप्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संचालित की गई है, जिससे गरीब मेधावी युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से निराश्रित हुई महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कार्ययोजना बनाई जा रही है। यह योजना निराश्रित बच्चों के लिए बनाई गई योजना की तर्ज पर होगी। कोरोना से निराश्रित हुई महिलाओं को किसी प्रकार की चिन्ता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार इनके साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ी है।

प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी ढंग से किया जाए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर उप्र लोक सेवा आयोग, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उप्र उच्चतर शिक्षा चयन आयोग तथा उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ इन आयोगोंध्बोर्ड के तहत विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों के सम्बन्ध में बैठक की। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा 74,000 पदों पर चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जाए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए सम्पन्न की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि खराब छवि वाले विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बिल्कुल न बनाया जाए। उन्होंने बड़ी परीक्षाओं को मण्डल स्तर पर और छोटी परीक्षाओं को जनपद स्तर पर आयोजित करने के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भर्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के समय अभ्यर्थियों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए अधिक दूरी न तय करनी पड़े। उन्होंने कहा कि हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षाएं नकलविहीन और पारदर्शी ढंग से आयोजित की जाएं।

मुख्यमंत्री ने सभी आयोगोंध्बोर्ड के अध्यक्षों से समय से भर्तियां करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन से जुड़े मामलों में सम्बन्धित अध्यक्ष मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे सम्पर्क कर समस्या का तुरन्त समाधान कराएं, ताकि भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ायी जा सके।

ज्ञातव्य है कि उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 30,000 पदों पर भर्तियां की जानी हैं, जबकि उप्र उच्चतर शिक्षा चयन आयोग द्वारा 17,000 पदों पर भर्ती की जाएंगी। इसी प्रकार उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 27,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, उप्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रो ईश्वर शरण विश्वकर्मा तथा उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष बीरेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

CM Office, GoUP
@CMOfficeUP

20 अगस्त को प्रस्तावित PET के लिए अभ्यर्थियों को उनकी सुविधा वाले जनपदों में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं।

सभी जनपदों में साफ-सुथरे रिकॉर्ड वाले संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाएं: #UPCM श्री @myogiadityanath जी

प्रदेश सरकार 100 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज वृक्ष के रूप में मान्यता दे रही : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वृक्ष प्रकृति के अनमोल रत्न हैं। इनकी रक्षा हम सबका दायित्व है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण को नुकसान से अनेक बीमारियां, मानव जीवन व जीव सृष्टि को त्रस्त करेंगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम सभी को 'वन है तो जीवन है, जल है तो कल है' के संकल्प के साथ पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रयास करने होंगे।

मुख्यमंत्री जनपद सुल्तानपुर में वृक्षारोपण जनान्दोलन–2021 के अन्तर्गत ग्रीन फील्ड पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे पर वृहद वृक्षारोपण कार्य को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने जनपद सुलतानपुर में वृक्षारोपण जनान्दोलन–2021 के अन्तर्गत ग्रीनफील्ड पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उन्होंने पीपल, पाकड़, बरगद, आंवला, गूलर और जामुन के पौधों का रोपण किया। जनप्रतिनिधियों को वृक्षारोपण जनान्दोलन–2021 के तहत पौधे वितरित किए। तत्पश्चात् एक्सप्रेस–वे के किनारे स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने बरगद के पेड़ का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन–अर्चन कर परिक्रमा की। वृक्षारोपण कार्यक्रम का निरीक्षण कर जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद, ग्राम पंचायत,मोहल्ले में वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है। वृक्षारोपण महा अभियान के तहत आज कई नये रिकॉर्ड बन रहे हैं। इनमें से एक रिकॉर्ड वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में आज 100 करोड़वां पौधा लगाने का है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में 5.71 करोड़, वर्ष 2018–19 में 11.77 करोड़, वर्ष 2019–20 में 22.60 करोड़, वर्ष 2020–21 में 25.87 करोड़ पौधों का रोपण कराया गया। विभागीय वृक्षारोपण के अलावा 5 करोड़ पौधों का रोपण किसानों व अन्य प्रदेशवासियों द्वारा किया गया है। वर्ष 2021–22 में 30 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण कराया जा रहा है। विगत 5 वर्षों में 100 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण जनान्दोलन–2021 के अन्तर्गत प्रातःकाल से ही प्रदेशवासियों द्वारा वृक्षारोपण का कार्य बड़े उत्साह से हो रहा है, सुबह से अब तक 9 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उनका सौभाग्य है कि आज उन्हें भारत की प्राचीन ऋषि परम्परा से सम्बन्धित पंचवटी, नवग्रह तथा नक्षत्र वाटिका के पवित्र पौधों का रोपण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सभी भारत की ऋषि परम्परा की विरासत से प्राप्त पवित्र वृक्षों का रोपण कर अपनी प्राचीन परम्परा से खुद को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने जनता से जनान्दोलन–2021 को सफल बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधे का रोपण करे। साथ ही, अपने सम्बन्धियों तथा परिचितों से भी कम से कम एक पौधा लगवाए। अलग–अलग प्रजातियों के पौधे लगाए जाएं तथा उनकी सुरक्षा भी की जाए। उन्होंने कहा कि पौधा भविष्य में वृक्ष बनकर प्रकृति के तंत्र को मजबूती प्रदान करने के साथ ही, फल, छाया, औषधि, लकड़ी उपलब्ध कराकर व्यक्ति की आवश्यकता भी पूरी करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहा है। यह एक्सप्रेस–वे राज्य के युवाओं को रोजगार देने, प्रदेश को समृद्ध तथा राज्य को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे के किनारे 5 स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित किये जाएंगे। इन क्लस्टर्स में फार्मा, आईटी, खाद्य प्रसंस्करण आदि से सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इससे प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी एवं रोजगार के अवसर सुलभ होंगे तथा वे स्वावलम्बन के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप राज्य को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के रूप में विकसित करने में सहायक होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन फील्ड पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे औद्योगिक गलियारा बनने के साथ ही, पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करेगा। यूपीडा द्वारा इस एक्सप्रेस–वे के किनारे स्थित एक प्राचीन वट वृक्ष का संरक्षण किया गया है। 100 वर्ष से अधिक पुराने इस वृक्ष को हेरिटेज वृक्ष की मान्यता दी गई है।

स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण तथा वायु प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए सभी लोग जागरूक हों : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों के अनुभव के दृष्टिगत वायु प्रदूषण के प्रबन्धन की कारगर रणनीति बनाते हुए आगामी शीत ऋतु में कार्य योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अग्रिम तैयारी कर ली जाए। साथ ही, भविष्य की रणनीतियों और माइक्रो प्लानिंग की प्रगति के सम्बन्ध में भी समीक्षा करते हुए कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण तथा वायु प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए सभी लोग जागरूक हों।

मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर प्रदेश के 17 नॉन अटेनमेण्ट शहरों (एनएसी) में वायु प्रदूषण नियंत्रण और वायु गुणवत्ता में सुधार के सम्बन्ध में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी सम्बन्धित विभाग व संस्थाएं प्रभावी पहल करते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेज को परस्पर साझा करें। उन्होंने इस सम्बन्ध में नगर निगम, वन विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी नॉन अटेनमेण्ट शहरों के लिए प्रदूषण स्रोतों के विस्तृत विश्लेषण करते हुए भविष्य की रणनीति बनायी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 लाख की ऊपर की आबादी वाले शहरों जैसे–लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा में वायु प्रदूषण में वृद्धि के चिन्हित कारणों को दूर किया जाए। गोरखपुर में वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा गुणवत्ता सुधार के लिए अपनायी गई रणनीति के प्रभावी परिणाम मिले हैं। इसी प्रकार की रणनीति एवं मॉडल एक्शन प्लान को अन्य शहरों के लिए भी लागू किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति की नियमित बैठकें आयोजित कर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मनोज सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण और वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए एयर क्वालिटी मानीटरिंग कमेटी की बैठक की जा चुकी है। इस बैठक में प्रत्येक नॉन अटेनमेण्ट शहर की वायु गुणवत्ता की स्थिति और अच्छी वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने बताया कि आगामी शीत ऋतु में ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) के कार्यान्वयन की अग्रिम तैयारी के लिए रणनीति बनाते हुए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर के नगर निगम, वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु हाइवे निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, पार्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, एण्ड–टू–एण्ड पेविंग आफ दि रोड, हाट स्पाट प्रबन्धन जैसी ढांचागत परियोजनाओं को कुशल व रणनीतिक तरीके से लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष गोरखपुर में 2020–21 में वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और अच्छी वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस रणनीति और दृष्टिकोण को अन्य नॉन अटेनमेण्ट शहरों के लिए भी लागू किया जाएगा। रायबरेली और खुर्जा में भी वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ने बताया कि सभी निर्माण परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित डस्ट एप पोर्टल पर अपना डस्ट कण्ट्रोल सेल्फ आडिट अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सम्बन्धित विभागों की संयुक्त टीमों द्वारा सेल्फ आडिट को क्रास वेरीफाई किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क की धूल को वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके लिए परिवहन के दौरान निर्माण सामग्री की यांत्रिक सफाई, छिड़काव और कवरिंग किए जाने पर जोर दिया जा रहा है।

'हर घर जल' योजना हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर जल जीवन मिशन के तहत संचालित की जा रही 'हर घर जल' योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह योजना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस योजना को लागू करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का केन्द्र व राज्य सरकार का लक्ष्य हासिल होगा। जन स्वास्थ्य को हासिल करने में स्वच्छ पेयजल की महती भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जनपदों में 'हर घर जल' योजना के तहत संचालित किये जा रहे सभी कार्यों को समय से पूरा कर जनता को लाभान्वित किया जाए। साथ ही, योजना के तहत किये गये कार्यों की प्रगति रिपोर्ट समय से अपलोड की जाए और प्रोजेक्ट का थर्ड पार्टी आडिट भी कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत घरों तक जल पहुंचाने के लिए बिछायी जाने वाली पाइप लाइन का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए और लोगों को कनेक्शन देने की कार्यवाही की जाए। पाइप की क्वालिटी पर कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने अगले दो महीने में 50 लाख कनेक्शन देने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्धता के साथ हासिल किया जाए। उन्होंने मुख्य सचिव स्तर पर इस योजना की साप्ताहिक समीक्षा किये जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण करते हुए प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति अनुराग श्रीवास्तव ने उन्हें 12 मार्च, 2021 के बाद निर्माण कार्य सम्बन्धी लक्ष्यों के विषय में अवगत कराया। इन लक्ष्यों में 38 हजार नये ग्रामों की डीपीआर बनाना, बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्रों के कार्यों की प्रगति, जल निगम द्वारा रेट्रो फिटिंग, निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराना इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने 'हर घर जल' योजना के तहत प्रदेश की कार्ययोजना के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री को नवीन कार्य प्रारम्भ करने के विभिन्न चरणों के विषय में भी जानकारी दी गयी। इनमें डिस्ट्रिक्ट वॉटर एण्ड सैनिटेशन मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) द्वारा ग्रामों की सूची, इम्पैनल्ड वेण्डर्स को उपलब्ध कराना, भूमि की व्यवस्था, वेण्डर सर्वे इत्यादि शामिल थे। उन्हें विभिन्न एजेन्सियों को आवंटित किये गये कार्यों की प्रगति के विषय में भी अवगत कराया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री को बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र पैकेजों के तहत आने वाले जनपदों की प्रगति के विषय में भी अवगत कराया गया। उन्हें उप्र जल निगम द्वारा संचालित रेट्रो फिटिंग, चालू योजनाओं तथा कनेक्शन की स्थिति के विषय में भी जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

मुख्यमंत्री को इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी (आईएसए) के विषय में अवगत कराया गया कि राज्य स्तर पर 165 आईएसए को सूचीबद्ध कर जनपद आवंटन की कार्यवाही की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'कैच द रेन' थीम के अन्तर्गत 22 मार्च, 2021 से जल शक्ति अभियान प्रारम्भ किया गया। इस योजना के तहत कराए जा रहे विभिन्न कार्यों, जिनमें वाटर बाडीज का पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण, तालाबों की डी–सिल्टिंग, छोटी नदियों का पुनरुद्धार इत्यादि शामिल हैं, की प्रगति के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी गयी।

मुख्यमंत्री को ग्रीष्मकालीन पेयजल सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु जनपद एवं विकासखण्डों में स्थापित किये गये कण्ट्रोल रूमों के विषय में भी अवगत कराया गया।

इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री डा महेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति अखण्ड प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चित्र प्रदर्शनी

वन महोत्सव सप्ताह (1–7 जुलाई) के अंतर्गत 30 करोड़ वृक्षरोपण के लक्ष्य के क्रम में सुल्तानपुर में पौधरोपण करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

प्रदेश में 04 जुलाई, 2021 को 25 करोड़ से अधिक पौधरोपण कर रिकॉर्ड बनाया गया

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक शिशिर, आईएएस द्वारा प्रकाशित
प्रभारी सम्पादक : डॉ. सीमा गुप्ता